

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency



Higher **Education in** India since Independence:

and its approach

Live Time- 11:00 AM

By-Jitendra Goswami

Paper 1st LIVE





I m, Jitendra Goswami

Ph.d(P),MCA,BCA

NET+GATE

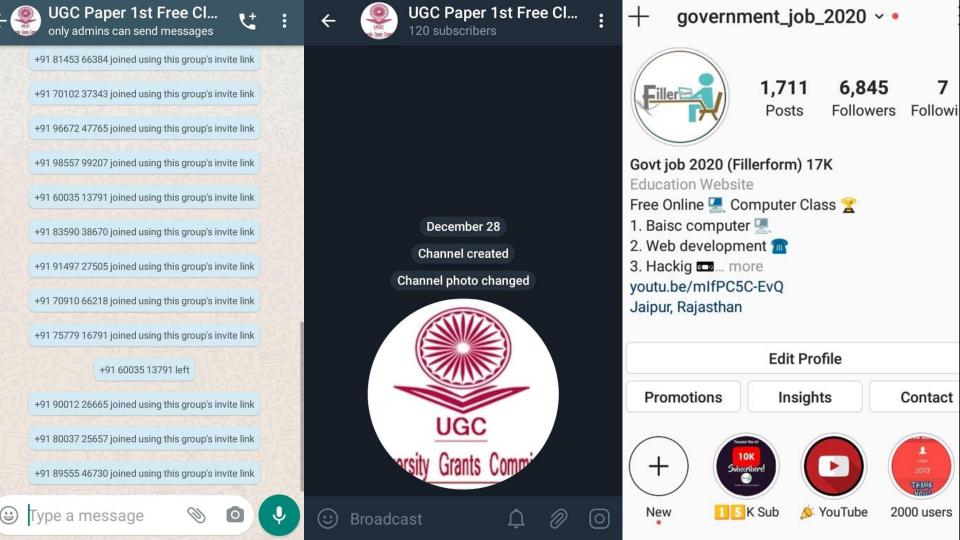
Google Student

1+ Year Online teaching







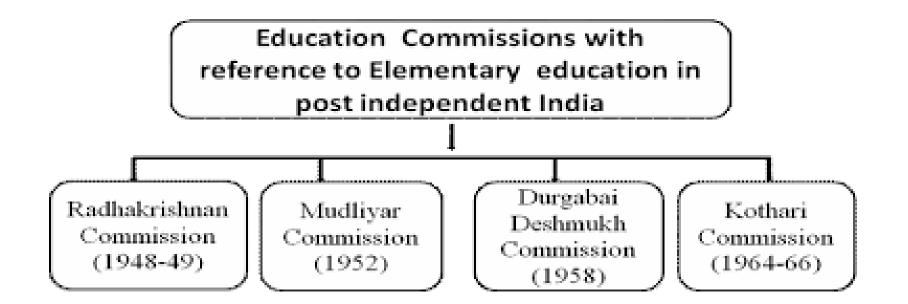


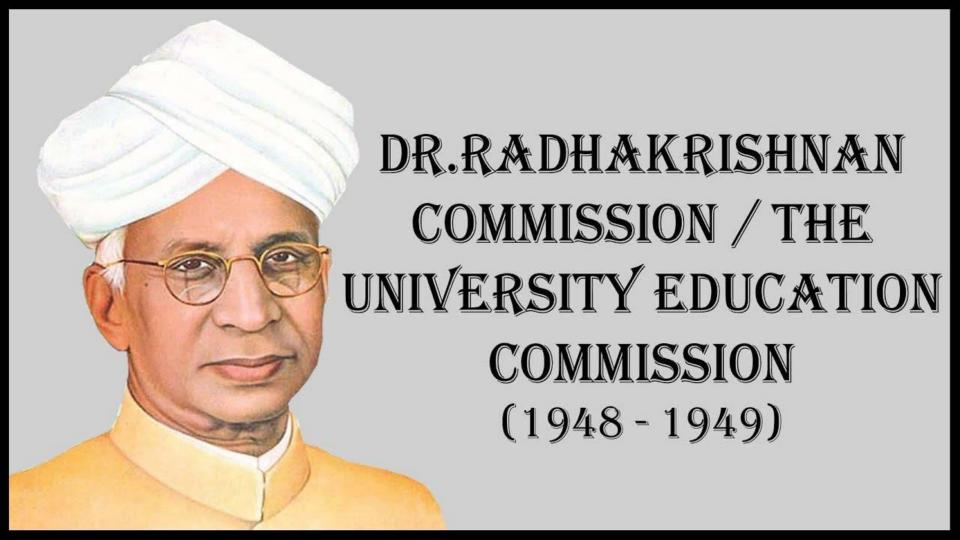
Mission JRF

UGC-NET Dec Exam 2021
Monday to Saturday

- 11 AM 1St Paper(Imp. Topic)
- ⁰⁷_{PM} 1St Paper(MCQ 25+)

- Sunday Class 2hr+
 - fillerform www.fillerform.info





विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग [राधाकृष्णन आयोग] 1948-49-

'Radhakrishnan Commission'

- २. इसने शारीरिक प्रशिक्षण एवं अन्य सामूहिक क्रियाओं पर भी बल दिया.
- ३. आयोग ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि माध्यमिक स्तर पर ही सामान्य शिक्षा के अलावा
- भौतिक वातावरण से पूर्ण परिचय के अतिरिक्त भौतिक तथा शारीरिक विज्ञान के मूल सिद्धांत की जानकारी दी
- ४. स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष होनी चाहिए यह इसी आयोग का सुझाव था.
- ५. विश्वविद्यालय पूर्व (pre-university) 12 वर्ष का अध्ययन.
- ६. विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए जो 11-11 सप्ताहों के तीन सत्रों में बंटी चाहिए.
- .८. एक विश्वविद्यालय अन्दान आयोग बनाए आये जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देख-रेख करे.

- 2. It also emphasized physical training and other group activities.
- 3. The Commission emphasized that apart from general education only at the secondary levelApart from full introduction to the physical environment, he gave the basic principles of physical and physical science
- 4. The duration of the graduate course should be three years, it was the suggestion of this commission.
- 5. 12 years of pre-university studies.
- 4. Universities should study at least 180 days in addition to examination days, which should be divided into three sessions of 11–11 weeks.
- .c. A University Grants Commission was created to look after university education in the country.

Mudaliar Commission/ Secondary Education Commission

- माध्यमिक शिक्षा के ढाँचे में सुधार के लिए डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सन् 1952 में ''माध्यमिक शिक्षा आयोग'' की स्थापना की गयी.
- ३. वस्तुनिष्ठ (MCQ) परीक्षण-पद्धति को अपनाया जाए.
- ४. संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए.
- ५. उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक core
- subject रहे जो अनिवार्य रहे जैसे—गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत etc.

- To improve the structure of secondary education, "Secondary Education Commission" was established in 1952 under the chairmanship of Dr. Laxman Swamy Mudaliar.
- 3. Objective (MCQ) testing method should be adopted.
- 4. Instead of giving numerical digits, the notation digits should be given.
- 5. Be a core subject in the syllabus of higher and higher secondary level education, which are compulsory Mathematics, General Knowledge, Art, Music etc.

shri k.l shrimali Commission(1954)



Shrimati durgabai deshmukh committee(1958)



Women Education

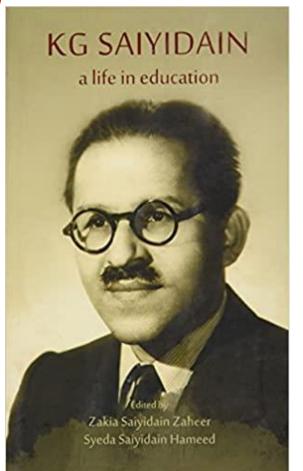
Educating Women and Girls



Previous committee

- National women education committee (1959) by Shreemati durgabai deshmukh
- Hansha mehta committee (1961) by Hansha mehta
- Bhakta Batsalam committee (1963) by Sree Bhakta Batsalam (C.M of Madras)

K.G. Saiyidain Committee-1960



Dr. Sampurnanand committee





कोठारी आयोग [राष्ट्रीय शिक्षा आयोग] 1964-66 Kothari Commission Recommendations

- Kothari commission में कुल 17 members थे इनमे सें 5 members विदेशी थे।
- ये 5 विदेशी सदस्य U.S.A,
 U.K, JAPAN, FRANCE, USSSR से थे।
- National education policy (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 1968 & 1986 को kothari commission की recommendations पर बनाया गया था।

www.filler

- •Kothari Commission was an ad-hoc commission set up by the Government of India.
- •Kothari Commission was formed on 14 July 1964.
- •On 29 June 1966, Kothari Commission was dissolved
- •Chairmanship Daulat Singh Kothar.

1.Defects in the existing education	
system	11.Three language formula
2. Aims of the education	12.Distance Education
3.Methods of teaching	13.Selective Admission
4.Textbook	14. Vocational Education
5.Curriculum	15.Education on Morals and
6.Educational structures and	Religion
standards.	16.University Autonomy
7.Physical welfare of students	17.Teacher Education
8.Education of women	18.Adult Education
9.Guidance and counselling	19.University – Aims, Objectives
10.Problems of Supervision and	and Functions
inspection	20.Administrative Problems
	21.Work Experience
	22.Higher Education – Enrollment
	23.Evaluation www.fillerform.com

शिक्षा का उद्देश्य पढाने के तरीके पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम शैक्षिक संरचना और मानक। छात्रों का शारीरिक कल्याण महिलाओं की शिक्षा मार्गदर्शन और परामर्श पर्यवेक्षण और निरीक्षण की समस्याएं तीन भाषा सूत्र दुरस्थ शिक्षा चयनात्मक प्रवेश व्यावसायिक शिक्षा नैतिकता और धर्म पर शिक्षा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता शिक्षक की शिक्षा प्रौढ शिक्षा विश्वविद्यालय - उद्देश्य, उद्देश्य और कार्य प्रशासनिक समस्याएँ कार्य अनुभव .com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968- National Policy on Education

पढ़ों, लिखा है दीवारों पर मेहनतकश का नारा पढ़ों, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा पढ़ों, अगर अंध विश्वासों से पाना है छुटकारा पढ़ों, किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा सामान्य रूप से देश के सभी भागों में शिक्षा का समान ढाँचा अपनाना लाभप्रद होगा जो कि 10+2+3 पर आधारित होगा.

- २. शिक्षा (Education) में निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए.
- ३. कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनायें बढ़ायी जाएँ.
- ४. विद्यालयी शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया जाए.
- ५. 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा.
- ६. विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण (equalisation).
- ७. पाठ्य-पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन.
- ८. राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना.

- 10 + 2 + 3 का मतलब है
- 1. कि छात्र दसवीं तक सेकेंडरी शिक्षा लेगा उसके बाद
- 2. 2 वर्ष तक सीनियर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त करेगा
- 3. उसके बाद अगले 3 वर्ष तक स्नातक की परीक्षा पास करेगा

किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र का स्नातक होना जरूरी है

नवीन शिक्षा-नीति 1986 – New Policy on Education 1986

आचार्य राममूर्ति समिति 1990 Acharya Ramamurti Committee

- 1. Semester System) अपनायी जाए.
- 2. Skill Development पर जोर.

यशपाल समिति 1992 Yashpal Committee Report

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1992 Modified National Policy on

Education

- . इसके अध्यक्ष श्री जनार्दन रेड्डी थे.
- २. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षकों का प्रावधान.
- ३. Operation Black Board और School Complex जैसी योजनाओं को जारी रखा जाए.
- ४. प्रौढ़ शिक्षा पर जोर और उसी के लिए "जिला साक्षरता अभियान" (District Literacy Movement-DLM) की सिफारिश.

For More Information

www.fillerform.info









info@fillerform.com

